[Shri Harikesh Bahadur]

In view of the importance of the subject, I would request the Hon'ble Minister to ensure at his level that conclusive action is taken.

(iv) NEED FOR DELIMITATION OF PARLIAMEMTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF HILLY DISTRICTS OF U.P.

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद व माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं नियोजन मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रान्तीय सरकारों से परामर्श कर देश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं विकास सम्बन्धी इकाइयों तथा विधान सभाई क्षेत्रों का निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियों व क्षेत्रफल के आधार पर किए जाने का निर्णय लेवें। जनसंख्या इनके निर्धारण का आधार नहीं होना चाहिए।

यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए प्रशासनिक एवं विकास सम्बन्धी इकाइयों को छोटा बनाया जाए। वर्तमान समय में देश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जनपदों, उपमन्डलों व विकास खण्डों का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि एक किनारे से जनपद के मुख्यालय तक पहुँचने में चार-पांच दिन का समय व बस के किराये में 150/- रु० तक एक व्यक्ति को खर्च करना होता है। यदि क्षेत्र विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड के प्रत्येक गांव का भ्रमण करना चाहे तो उन्हें दो माह से भी अधिक का समय लगेगा। इन पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश भागों में सड़क यातायात व संचार सुविधाओं का अभाव है। प्रशासनिक एवं विकास कार्यों के संचालन हेतु नियुक्त अधिकारी विधिवत् तरीके से विकास कार्यों का निरीक्षण कर नहीं पाते हैं।

पर्वतीय भागों में संसदीय एवं विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र भी बहुत बड़े-बड़े हैं। मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र भी दो जनपदों से मिलकर बना हुआ है। मैं तीन साल तक लगातार भी भ्रमण करूं तो शायद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पहुँच पाऊंगा। विधान सभा क्षेत्र भी बहुत बड़े-बड़े हैं। दूर-दूर छिटके हुए गांव प्राकृतिक बाधायें, नदी, नाले, जंगल व पहाड़ आदि चुनौती तो अवश्य हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं है।

अतः गृह मंत्रालय को चाहिए कि वे चुनाव आयोग से परामर्श कर पहले तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को पर्वतीय भागों में छोटा बनावें, यदि यह कार्य संभव न भी होवे तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों के विधान सभाई क्षेत्रों का गठन मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड या हिमाचल के पैटर्न पर होना चाहिए।

(v) NEED FOR GIVING PROPRIETORY RIGHTS AND OTHER FACILITIES TO THE BHAKRA DAM OUSTEES BY HARYANA GOVERNMENT.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : Mr. Deputy-Speaker, the Bhakra Dam oustees made significant sacrifices for the cause of the motherland as they were forced to leave their hearths and homes for settling down in district Hissar of Haryana, the then Punjab. Consequent upon the completion of Bhakra Dam Projects, the distances between various points in Bilaspur district, Una and Hamirpur tehisils of the then Kangra district increased manifold as many bridges and roads connecting these